RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 185
दि. 09.04.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

केरल में लोकतंत्र का महासंग्राम: 140 सीटों पर निर्णायक मुकाबला, तीन गठबंधनों के बीच सियासी प्रतिष्ठा दांव पर

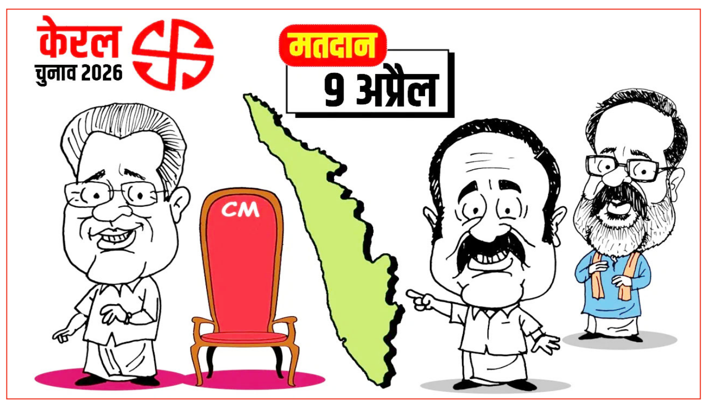

(जीएनएस)। केरल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां 9 अप्रैल को होने जा रहा मतदान न सिर्फ 140 विधानसभा सीटों की तस्वीर तय करेगा, बल्कि राज्य के राजनीतिक भविष्य की दिशा भी निर्धारित करेगा। लगभग 2.71 करोड़ मतदाता—जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं—883 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता बरकरार रखने की कवायद भर नहीं है, बल्कि विचारधाराओं, विकास मॉडल, सामाजिक समीकरणों और धार्मिक-सांस्कृतिक विमर्शों के बीच एक व्यापक टकराव का प्रतीक बन चुका है।

राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला तीन बड़े गठबंधनों के बीच है—वामपंथी दलों के नेतृत्व वाला एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए। केरल की राजनीति पारंपरिक रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच घूमती रही है, जहां हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया रही है। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। एक ओर जहां एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूडीएफ सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। दूसरी ओर, एनडीए पहली बार गंभीरता से इस द्विध्रुवीय राजनीति को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरा है।

चुनावी प्रचार के दौरान केरल में राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के लिए कई रैलियां कीं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूडीएफ के समर्थन में जनसभाएं कीं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एलडीएफ के अभियान की अगुवाई करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस व्यापक प्रचार अभियान ने चुनाव को और भी अधिक दिलचस्प और बहुआयामी बना दिया है।

अगर एलडीएफ की बात करें तो उसका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष उसका संगठित कैडर बेस और जमीनी पकड़ है। खासकर ग्रामीण इलाकों में वामपंथी दलों की मजबूत उपस्थिति उन्हें बढ़त दिला सकती है। राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लेकर एलडीएफ सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हें वह अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण एंटी-इन्कम्बेंसी एक बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। विपक्ष लगातार गोल्ड स्मगलिंग केस और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर सरकार को घेरता रहा है, जिसका असर मतदाताओं के रुझान पर पड़ सकता है।

वहीं, यूडीएफ के पास परंपरागत वोट बैंक का मजबूत आधार है, जिसमें मुस्लिम और ईसाई समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांग्रेस इस चुनाव में एलडीएफ की कथित 'तानाशाही' और प्रशासनिक विफलताओं को मुद्दा बना रही है। हालांकि, यूडीएफ के भीतर की गुटबाजी उसके लिए चुनौती बन सकती है। कई मौकों पर यह देखा गया है कि आंतरिक मतभेद चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, और इस बार भी यह एक निर्णायक कारक साबित हो सकता है।

तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रहा एनडीए इस चुनाव में खासा सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में केरल में अपने वोट शेयर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की है। पंचायत और लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। एनडीए का फोकस खास तौर पर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने पर है, और सबरीमाला जैसे मुद्दों ने उसे कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ भी पहुंचाया है। इसके साथ ही, विकास और बुनियादी ढांचे के वादों के जरिए बीजेपी खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है।

इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो हर गठबंधन ने अपने-अपने तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश की है। एलडीएफ ने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी ताकत बताया है, वहीं यूडीएफ ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता को प्रमुख मुद्दा बनाया है। बीजेपी ने दोनों प्रमुख गठबंधनों को घेरते हुए खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया है। सबरीमाला मंदिर से जुड़े विवाद, गोल्ड स्मगलिंग केस, बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी ढांचे का विकास जैसे मुद्दे इस चुनाव के केंद्र में रहे हैं।

मतदान की तैयारियों की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे राज्य में 30,495 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 24 सहायक बूथ भी शामिल हैं। कासरगोड, कन्नूर, पलक्कड़, मलप्पुरम और एर्नाकुलम जैसे जिलों में नए पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके। खास बात यह है कि 352 पोलिंग बूथों का संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जबकि 37 बूथों का संचालन दिव्यांग कर्मियों के हाथों में होगा। यह पहल लोकतंत्र में समावेशिता और भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 76 हजार पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, और हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।

केरल की राजनीति हमेशा से ही जागरूक मतदाताओं और उच्च मतदान प्रतिशत के लिए जानी जाती रही है। यहां के मतदाता केवल जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मुद्दों और नीतियों के आधार पर भी अपने फैसले लेते हैं। यही कारण है कि केरल का चुनावी परिणाम अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए दिलचस्प और अप्रत्याशित होता है।

इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर एलडीएफ सत्ता में वापसी करता है, तो यह राज्य की पारंपरिक सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति को तोड़ देगा। वहीं, अगर यूडीएफ जीत हासिल करता है, तो यह उसके लिए एक मजबूत वापसी होगी। दूसरी ओर, अगर एनडीए अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।

अंततः, 9 अप्रैल को होने वाला मतदान केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव है, जिसमें हर मतदाता की भूमिका निर्णायक है। जनता अपने वोट के माध्यम से यह तय करेगी कि आने वाले पांच वर्षों में राज्य की बागडोर किसके हाथों में होगी। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि केरल की जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है और किस गठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है।

अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम: दो सप्ताह के लिए युद्ध रुका, पाकिस्तान और वैश्विक कूटनीति सक्रिय

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अमेरिका और ईरान के बीच 39 दिन से जारी संघर्ष को दो सप्ताह के लिए विराम दे दिया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला वैश्विक शांति के लिए राहत लेकर आया है और कई देशों की कूटनीतिक सक्रियता को उजागर करता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेकशियन ने इसे अपने देश के मूल सिद्धांतों और शहीदों की शहादत का परिणाम बताते हुए कहा कि देश की एकता और जनता की दृढ़ता ने इसे संभव बनाया।

संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, जिन्होंने बताया कि ईरान 15 बिंदुओं पर सहमति को तैयार हुआ है। इस कदम से पूरे विश्व ने राहत की सांस ली, क्योंकि लंबे समय से मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ रही थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर रहा है, और समुद्री मार्ग होर्मुज में यातायात सामान्य करने में सहयोग देगा।

पाकिस्तान की भूमिका इस संघर्ष विराम में निर्णायक रही। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है और दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर अपने मुद्दों का समाधान करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेकशियन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

संघर्ष विराम के साथ ही अमेरिका ने स्पष्ट किया कि ईरान को हथियार देने वाले किसी भी देश पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक हथियार और ऊर्जा व्यापार को प्रभावित करेगा। इसके बावजूद ट्रंप ने आश्वस्त किया कि अमेरिका ईरान के साथ सहयोग और आपूर्ति के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाएगा, और मध्यपूर्व के लिए यह एक स्वर्णिम काल साबित होगा।

हालांकि फारसी मीडिया में अफवाहें फैल रही थीं कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु संवर्धन की इजाजत दे दी है, जिसे ट्रंप ने स्पष्ट रूप से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तैनात रह सकते हैं, जबकि ईरान का 90 फीसदी तेल इसी मार्ग से गुजरता है और यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस बीच, संघर्ष विराम का दायरा पूरी तरह से नहीं फैला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा और हिज्बुल्ला के खिलाफ उनकी सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने दावा किया कि लेबनान को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

संघर्ष विराम के तुरंत बाद इराक ने अपने एयरपोर्ट और एयरस्पेस को खोल दिया। नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख बंकिन रेकानी ने बताया कि बगदाद और इर्बिल एयरपोर्ट जंग के कारण बंद थे, लेकिन अब आवागमन फिर से सुचारू हो गया है। इस प्रकार, अमेरिका और ईरान के बीच यह दो सप्ताह का संघर्ष विराम केवल युद्धविराम ही नहीं है, बल्कि वैश्विक कूटनीति, पाकिस्तान की मध्यस्थता और मध्यपूर्व के स्थिरता प्रयासों का प्रतीक भी बन गया है। आने वाले समय में दोनों देशों की बैठकों और वार्ता के परिणाम पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए स्थायी शांति की दिशा तय करेंगे।

हिरासत में मौत पर सख्त संदेश: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप बरकरार रखा

(जीएनएस)। न्यायपालिका ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के रखवालों को भी कानून के दायरे में ही रहकर काम करना होगा। 2014 के चर्चित कस्टोडियल डेथ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाते हुए आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप को बरकरार रखा है। अदालत ने यह माना कि प्रथम दृष्टया ऐसे पर्याप्त संकेत और साक्ष्य मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि हिरासत में युवक के साथ अमानवीय व्यवहार और गंभीर यातना हुई थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में विस्तृत ट्रायल आवश्यक है और इसे किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता।

यह मामला एग्नेलो वाल्डारिस नाम के 25 वर्षीय युवक की मौत से जुड़ा है, जिसकी अप्रैल 2014 में मुंबई के वडाला रेलवे पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस समय यह घटना काफी सुर्खियों में रही थी और मानवाधिकार संगठनों सहित आम जनता के बीच भी आक्रोश का कारण बनी थी। अब वर्षों बाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर इस मामले को केंद्र में ला दिया है और न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को रेखांकित किया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एग्नेलो वाल्डारिस को गैर-कानूनी हिरासत में रखकर बुरी तरह पीटा गया था। अदालत ने विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जो यह संकेत देते हैं कि उसके साथ शारीरिक हिंसा की गई थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप को हटाना उचित नहीं होगा और मामले का ट्रायल होना चाहिए।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि अदालत ने कस्टोडियल डेथ जैसे मामलों में साक्ष्यों की प्रकृति पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष या चश्मदीद गवाह मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि घटना आमतौर पर पुलिस हिरासत के भीतर होती है, जहां बाहरी लोगों की पहुंच नहीं होती। इसलिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का महत्व बढ़ जाता है और उन्हें गंभीरता से परखा जाना चाहिए। यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित करती है।

अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह घटना अप्रैल 2014 की है, जब वडाला जीआरपी पुलिस ने चेन स्नैचिंग के शक में एग्नेलो वाल्डारिस और तीन अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था। एग्नेलो के पिता लियोनार्ड वाल्डारिस ने पुलिस के अनुरोध पर अपने बेटे को खुद उनके हवाले किया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि केवल पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने एग्नेलो के परिवार को उसके जीवित बेटे के बजाय उसकी लाश सौंपी। परिवार और अन्य गवाहों के आरोप बेहद गंभीर और चिंताजनक थे। उनका कहना था कि एग्नेलो को हिरासत में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। आरोपों के मुताबिक, उसे बेल्ट और डंडों से पीटा गया, नग्न कर मारपीट की गई, उल्टा लटकाया गया और यहां तक कि उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया। इन आरोपों ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी गहरी चिंता पैदा की। हालांकि, पुलिस विभाग लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा और अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करता रहा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने पुलिस के दावों को कमजोर कर दिया। यही कारण है कि विशेष ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2022 में इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला चलाने का आदेश दिया था, जिसे अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है। यह फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पुलिस तंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की हिरासत में सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिरासत में मौत जैसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालय पहले भी कई बार सख्त रुख अपना चुके हैं, और यह फैसला उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही, यह मामला यह भी दर्शाता है कि न्याय मिलने में भले ही समय लगे, लेकिन अगर साक्ष्य मजबूत हों और परिवार न्याय के लिए संघर्ष करता रहे, तो अंततः न्यायिक प्रणाली अपना काम करती है। एग्नेलो वाल्डारिस के परिवार के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, हालांकि अंतिम न्याय अभी ट्रायल के बाद ही तय होगा।

असम में सियासी संग्राम का निर्णायक दिन: क्या बीजेपी बनाएगी इतिहास या कांग्रेस करेगी वापसी?

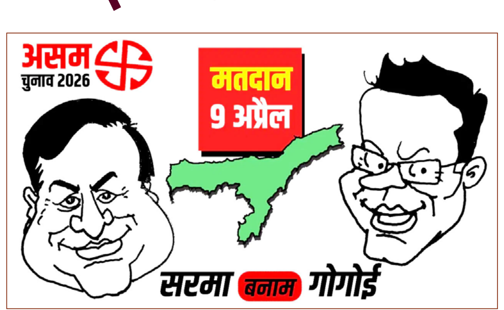

(जीएनएस)। असम की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां 126 विधानसभा सीटों के लिए होने वाला मतदान राज्य की सत्ता की दिशा तय करेगा। गुरुवार को होने जा रहे इस चुनाव में करीब 2.50 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 722 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पिछले एक दशक के राजनीतिक समीकरणों, विकास कार्यों और जनभावनाओं का व्यापक परीक्षण भी है। भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस दस साल के वनवास को समाप्त कर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा है। हालांकि, क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक ताकतों की मौजूदगी इस मुकाबले को और भी जटिल और दिलचस्प बना रही है। चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई जैसे बड़े चेहरे अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत आजमा रहे हैं।

असम की राजनीति में पिछले दस वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2016 में भाजपा ने पहली बार राज्य में सत्ता हासिल कर कांग्रेस के लंबे शासन का अंत किया था। इसके बाद 2021 में भी भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी और अब वह तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। भाजपा का पूरा जोर विकास, बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर रहा है। पार्टी का दावा है कि उसने राज्य में स्थिरता और प्रगति का नया अध्याय लिखा है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर, कांग्रेस इस चुनाव को अपनी सियासी पुनर्स्थापना के अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी का मानना है कि भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती असंतोष की भावना उसे फायदा पहुंचा सकती है। बेरोजगारी, महंगाई, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही, उसने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक व्यापक विपक्षी गठबंधन तैयार किया है, जिससे उसे चुनाव में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या और उनकी विविधता भी इस बार ध्यान आकर्षित कर रही है। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। एआईयूडीएफ, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई (एम), एपीएचएलसी, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा, 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकते हैं।

मतदाताओं की बात करें तो इस बार असम का चुनाव कई मायनों में खास है। करीब 6.42 लाख मतदाता पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण का संकेत है। वहीं, 80 वर्ष से अधिक आयु के 2.50 लाख मतदाता और 100 वर्ष से अधिक उम्र के 2,466 मतदाता लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग ले रहे हैं, जो इस प्रक्रिया की व्यापकता और समावेशिता को दर्शाता है। इसके अलावा, 2.05 लाख दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

महिलाओं की भागीदारी भी इस चुनाव में उल्लेखनीय है। कुल 59 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस ने 14 और भाजपा ने 7 महिलाओं को टिकट दिया है। यह आंकड़ा भले ही बहुत बड़ा न हो, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

मतदान की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राज्य के 35 जिलों में 31,490 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सीआरपीएफ के जवानों की व्यापक तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

अगर प्रमुख मुकाबलों की बात करें तो जालुकबारी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का मुकाबला कांग्रेस की बिदिशा नियोग से है। यह सीट न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह चुनाव के व्यापक परिणाम का संकेत भी दे सकती है। वहीं, जोरहाट सीट पर गौरव गोगोई और भाजपा के हितेंद्रनाथ गोस्वामी के बीच मुकाबला भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल का बिनाकांडी सीट से चुनाव लड़ना भी इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। असम का यह चुनाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। पूर्वोत्तर में भाजपा की बढ़ती पकड़ और कांग्रेस की घटती ताकत के बीच यह चुनाव एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। अगर भाजपा यहां जीत की हैट्रिक बनाती है, तो यह उसके लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी और पूर्वोत्तर में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। वहीं, अगर कांग्रेस वापसी करती है, तो यह उसके लिए न केवल असम में बल्कि पूरे देश में एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है।

संपादकीय

एमएसपी हकीकत न बनने से मजबूरी में बिक्री

कहने को तो देश डिजिटल क्रांति के दौर में पहुंच चुका है और वित्तीय लेनदेन से लेकर तमाम क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक वरदान साबित हो सकती है। लेकिन हमें यह मानकर चलना चाहिए कि देश का परंपरागत किसान डिजिटल सुविधाओं के उपयोग में खुद को सहज महसूस नहीं करता। आधुनिक डिजिटल तकनीक का प्रयोग नई पीढ़ी की सोच के अनुरूप है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इसके उपयोग में खुद को असहज पाती है। कमोबेश किसानों के कल्याण के लिए बनाये गए मंडी पोर्टलों पर भी यही बात लागू होती है। जाहिरा तौर पर किसानों के लिये मंडी पोर्टलों का उपयोग आसान होना चाहिए। बाकायदा किसानों को डिजिटल साक्षर बनाने की मुहिम चलाने की जरूरत भी है। सही मायनों में डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि उपजों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना था। लेकिन हरियाणा में जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। दरअसल, हम एक आम किसान से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह शहरी लोगों की तरह पोर्टलों, पासवर्डों और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों के जाल का सहजता से उपयोग कर सके। यही वजह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ उठाने के लिये उसे एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर की मंडियों से द ट्रिब्यून में प्रकाशित हालिया रिपोर्टों से एक जैसा पैटर्न नजर आया है। अब राज्य में फसलों की बिक्री के लिये अनिवार्य पोर्टल- ई-खरीद और मेरी फसल,मेरा ब्योरा यानी एमएफएमबी- साइट क्रैश, डेटा विसंगतियों और सत्यापन की विफलताओं से ग्रस्त है। जिससे कई तरह की समस्याओं से किसानों को रूबरू होना पड़ रहा है। यहां तक कि कई जिलों में, किसानों को गेट पास तक नहीं दिए गए हैं। वजह यह बतायी जा रही है कि किसानों का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है। कई बार अंतिम व महत्वपूर्ण क्षणों में सर्वर ने काम नहीं किया। जिसका खमियाजा फसल बेचने आने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है।

दरअसल, ऐसी अनेक तकनीकी जटिलताओं के परिणाम तात्कालिक व गंभीर बताये जाते हैं। किसानों की फसल तो बिक्री के लिये तैयार है, लेकिन कतिपय कारणों से उसे मंडियों में प्रवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है किसान अपने खून-पसीने की फसल निजी व्यापारियों को बेचने को विवश हो जाते हैं। किसान की मजबूरी ये होती है कि वह जल्द से जल्द फसल बेचना चाहता है। उसे अपने पहले के खर्च निकालने हैं और अगली फसल की तैयारी करनी है। जिसके चलते वह तुरंत भुगतान की आस में कम दाम में भी व्यापारियों को फसल बेचने को बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं, लेकिन फसल की आवक का एक छोटा हिस्सा ही खरीद पायी हैं। जो फसल खरीद के वायदे और वास्तविक तैयारी के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। कुछ आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। विशेष रूप से, हरियाणा में गेहूं की खरीद को 80 लाख टन से घटाकर 72 लाख टन करने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उन्हें आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि जो अनाज एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है, उसे किसान व्यापारियों को एमएसपी से 400 से पांच सौ रुपये कम दाम पर बेचने को मजबूर है। यानी एमएसपी के मूल उद्देश्य के विपरीत यह किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि डिजिटलीकरण का लक्ष्य व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। लेकिन इस प्रणाली की उपयोगिता तभी है जब सर्वर ठीक से काम कर रहा हो। साथ ही लोग इसका उपयोग बेहतर ढंग से करना जानते हों। यह प्रक्रिया छोटे और गरीब व निरक्षर किसानों को प्रोसेस से बाहर कर देती है। जिनकी सेवा का दावा व्यवस्था अक्सर करती है। एक विसंगति यह भी कि इसमें कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। पोर्टल के फेल होने पर खरीद रुक जाती है। यदि एमएसपी का लाभ कमजोर डिजिटल प्रणाली की वजह से किसान को नहीं मिलता, तो यह किसानों का सुरक्षा कवच नहीं रह जाता है।

ममता का विजय रथ रोकने को भाजपाई चक्रव्यूह

> “ वामपंथ के किले को ढहाकर सत्ता में आईं ममता बनर्जी लगातार तीन बार से मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी टीएमसी कई मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है।

पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार मुकाबला बहुकोणीय लग रहा है। मुख्य मुकाबला प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के बीच है। कई मामलों में बेहद अहम इस राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य में भाजपा के मुकाबले अन्य पार्टियों की एकता नहीं बन पायी। अनेक वामपंथी संगठनों को इस बात का मलाल है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर नहीं लड़ा जा रहा है। वामपंथ के किले को ढहाकर सत्ता में आईं ममता बनर्जी लगातार तीन बार से मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी टीएमसी कई मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है।

पड़ोसी राज्य असम की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी कुछ समीकरण समान लग रहे हैं। असम में पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, फिर से कुर्सी संभालने की जुगत में हैं तो यहां कभी ममता के करीबी रहे सियासी धुरंधर उनकी राजनीतिक पिच को खोदने में लगे हैं। बात चाहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की हो या फिर अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हुमायूं कबीर की। इन सबके बीच कांग्रेस अपने तरीके से जोर लगा रही है और वामपंथियों को उम्मीद है कि उनका वोट शेयर इस बार बढ़ेगा। अलग-अलग सियासी दलों के मैदान में उतरे होने से मुद्दे भी उतने ही ज्यादा हैं। यानी मुद्दों की खिचड़ी को पकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ‘माछ-भात’ को राजनीति की ‘डाइनिंग टेबल’ पर परोसे जाने की भी कोशिश है।

चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग ने राज्य के कई शीर्ष अफसरों का तबादला कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। राज्य सरकार इन तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट भी गयी, हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। इधर, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा जोर लगाती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार 15 दिन राज्य में रहे। शाह भाजपा के मुख्य चेहरा शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान भी मौजूद रहे। अधिकारी, ममता को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं और दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अभी किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है और वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनके विकास के एजेंडे के नाम पर वोट मांगेगी।

चुनावी रण में रोचक मुद्दों के बीच, पश्चिम बंगाल का मशहूर ‘माछ-भात’ (मछली की तरीदार सब्जी और चावल) को राजनीति की मेज पर लाने की कोशिश हो रही है। भाजपा जहां हिंदुत्व को मुद्दा बनाने की शुरू से ही कोशिश में रही है, वहीं टीएमसी ‘माछ-भात बंगाली’ को मुद्दा बना रही है। इस मसले का कोई विरोध कर भी नहीं सकता। असल में, टीएमसी ने इस भावना को सियासी धार देने की कोशिश करते हुए तर्क दिया है कि भाजपा हिंदी भाषी व उत्तर भारत की शाकाहार-समर्थक राजनीति से जुड़ी है और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के साथ उसका कोई मेल नहीं। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल प्रवास के दौरान भी तंज कसा कि आप राजनीति की रोटियां सेकने आए हैं तो माछ-भात का लुत्फ जरूर उठाएं। एसआईआर की सुप्रीम जांच के आदेश के बीच, न्यायिक अधिकारियों की घेराबंदी को भाजपा जोरशोर से उठा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में इसे उठा रहे हैं।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में सबसे मुखर रहने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा को कई अन्य मुद्दों पर भी घेर रही हैं। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे को पकड़े हुए है। कांग्रेस और वामपंथियों की कोशिश स्थानीय मुद्दों को हवा देने की है। सत्ता-विरोधी लहर की चुनौती भी झेल रही ममता के भतीजे अभिषेक ‘फायर ब्रांड’ नेता की तरह उभरे हैं। उनकी इस छवि को जनता कितना तवज्जो देगी, यह तो समय बताएगा।

हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाने की कूवत रखती तो दिख रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर द्वारा गठित आम जनता उन्नयन पार्टी का समर्थन किया है। कबीर ने ‘बाबरी’ मस्जिद की नींव रखकर मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डालने की कोशिश की है। सियासत के इस बदलाव के बीच कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या का मामला भी मुद्दा बना है। पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने मृतक छात्रा की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष से है। देखना होगा कि मुद्दों की खिचड़ी में ‘माछ-भात बंगाली’ क्या गुल खिलाएगा।

प्रेरणा

ज्ञान की तपस्याः लक्ष्य के लिए समर्पित एक महान आत्मा

छात्र जीवन को अक्सर जीवन का सबसे सुनहरा और आनंदमय समय कहा जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो इस समय को केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि अपने बड़े उद्देश्य की नींव रखने के लिए जीते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और समाज परिवर्तन का अद्भुत उदाहरण है। जब वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंचे, तब उनके सामने न केवल एक नई दुनिया थी, बल्कि एक ऐसा अवसर भी था, जिसके माध्यम से वे अपने जीवन के उद्देश्य को साकार कर सकते थे।

अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अंबेडकर जी का जीवन पूरी तरह अनुशासन और परिश्रम से भरा हुआ था। वे रोजाना सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचते और उसके बंद होने तक निरंतर अध्ययन में लीन रहते थे। यह केवल एक आदत नहीं थी, बल्कि उनके भीतर जल रही उस आग का परिणाम था, जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए पढ़ाई केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने का एक शक्तिशाली हथियार थी।

उनकी इस निरंतरता और समर्पण को देखकर लाइब्रेरी का एक कर्मचारी भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि जहां अन्य छात्र पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे, वहीं अंबेडकर जी हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। एक दिन उसने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर वे इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि उनकी उम्र के अन्य लोग जीवन का आनंद भी लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अंबेडकर जी ने जिस सादगी और गहराई से दिया, वह आज भी हर विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उन्होंने कहा कि उनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए पढ़ रहे हैं। उनके शब्दों में वह दृढ़ निश्चय झलकता था, जिसने उन्हें आगे चलकर भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नेता बनाया। यह उत्तर केवल एक सामान्य जवाब नहीं था, बल्कि उस सोच का प्रतिबिंब था, जिसने उन्हें महान बनाया।

अंबेडकर जी का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना भी है। आज के समय में, जब शिक्षा को अक्सर केवल नौकरी पाने का माध्यम माना जाता है, अंबेडकर जी का यह विचार हमें एक नई दिशा देता है। वे हमें यह समझाते हैं कि यदि हमारे पास ज्ञान है, तो हमें उसे समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। उनकी शिक्षा के प्रति लगन और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया, जिसकी गूंज आज भी पूरे विश्व में सुनाई देती है।

आज के युवाओं के लिए अंबेडकर जी का यह जीवन प्रसंग एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह हमें बताता है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम और अनुशासन की आवश्यकता होती है।

इसके साथ ही, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग समाज के उत्थान के लिए भी करना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हमारी सफलता का अर्थ और भी गहरा हो जाता है।

अंबेडकर जी की यह सोच आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाती है, जब समाज में कई प्रकार की असमानताएं और चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में, यदि युवा वर्ग उनके आदर्शों को अपनाए, तो वे न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

यह प्रेरणादायक प्रसंग हमें यह याद दिलाता है कि महानता किसी एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह निरंतर प्रयास, अनुशासन और समर्पण का परिणाम होती है। अंबेडकर जी ने अपने छात्र जीवन में जो आदर्श स्थापित किए, वे आज भी हर विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शक हैं।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है, जो हमें अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने की सीख देती है। उनका यह संदेश कि “मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए पढ़ रहा हूं,” आज भी उतना ही प्रभावी है, जितना उस समय था। यदि हम इस विचार को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा जीवन सार्थक होगा, बल्कि हम समाज के लिए भी कुछ सकारात्मक योगदान दे पाएंगे।

कभी कुछ न करके भी देखो...अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच 5 Star स्ट्रैटजी से अब चीन दुनिया पर राज करेगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी वो तो गुजर चुकी है। जिस हमले को लेकर उन्होंने दावा किया था वो हमला भी नहीं हुआ। बैकफुट पर वो आ गए हैं और सब की नजरें इस वक्त उन देशों पर टिकी हुई हैं जो देश युद्ध में इनवॉल्व हैं। अमेरिका का क्या रुख होगा? डॉनल्ड ट्रंप अब कौन सा फैसला लेंगे। हर कोई इसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। बहरहाल जब डेडलाइन क्रॉस होनी थी आज सुबह 5:30 बजे तक उससे पहले एक बड़ी खबर आई और वो ये कि ईरान के ऑयल अब खारक आइलैंड पर हमला किया गया है। गल्फ कंट्रीज में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की और होर्मुज समुद्री मार्ग नहीं खोला तो ईरान पर इतने हमले करेंगे कि वह पाषाण युग में चला जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटे बाद अचानक से सीजफायर का ऐलान हो जाता है। आज आपको 2019 में चर्चित हुए एक ऐड की याद दिलाते हैं। इस विज्ञापन में दिखाया गया है कि युवक कैडबरी 5स्टार चॉकलेट बार का आनंद ले रहा है, तभी महिला उससे अपनी छड़ी उठाने के लिए कहती है जो उससे गलती से गिर गई थी, जिस पर वह हां कह देता है लेकिन कुछ नहीं करता। फिर बुजुर्ग महिला छड़ी उठाने के लिए उठती है। ठीक उसी क्षण, एक विशाल पियानो उस बेंच पर गिरता है जहाँ वह कुछ देर पहले बैठी थी। इसके बाद वह युवक को धन्यवाद देती है कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसी वजह से उसकी जान बच गई। विज्ञापन चॉकलेट उत्पाद की नई टैगलाइन के साथ समाप्त होता है- कभी कुछ न करके भी देखो और 5 स्टार खाओ। कुछ मत करो। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों एक देश और उसके राष्ट्रपति के साथ मैच कर रहा है। न उस देश ने अपनी फौज उतारी, न कोई बमबारी की और न ही कोई बड़ा बयान देकर फालतू का हो हल्ला मचाया। दुनिया ईरान के मामले में उलझी रही, लेकिन चीन ने चालाकी से किनारे होकर ईरान से सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रखा। सच तो यह है कि अगर कोई एक देश है जिसने खुद को इस लड़ाई-झगड़े से पूरी तरह दूर रखा है, तो वो चीन ही है। चीन की इसी चुपचाप बैठकर तमाशा देखो वाली नीति की आजकल पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने तो इसे अपने कवर पेज पर छापा है। उन्होंने चीन की इस चाल को एक पुरानी कहावत के जरिए समझाया हैः जब आपका दुश्मन खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुन रहा हो या गलती कर रहा हो, तो उसे टोककर उसकी गलती सुधारने की कोशिश कभी मत करो। चीन बस वही कर रहा है। दूसरों को उलझते देख रहा है और खुद चुपचाप अपना फायदा निकाल रहा है।

जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग तेज हुई, तो सबको लगा था कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें कूदेंगी। लेकिन चीन ने खुद को इससे बिल्कुल दूर रखा। उसकी प्रतिक्रिया बहुत ठंडी रही; यहाँ तक कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस लड़ाई पर सार्वजनिक रूप से एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। अमेरिका को लगा था कि वह ईरान की सरकार बदल देगा और उसके परमाणु प्रोग्राम को रोक देगा, लेकिन उल्टा वह खुद एक कभी न खत्म होने वाली जंग में फंस गया। नतीजा क्या निकला? अमेरिका पर युद्ध का भारी कर्ज चढ़ गया, खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्तों में खटास आ गई और अपने ही साथी (नाटो) देशों के साथ अनबन शुरू हो गई। चीन के लिए इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती थी!

इस बात को ‘द इकोनॉमिस्ट’ के कवर पर बहुत ही शानदार ढंग से दिखाया गया है। इसकी हेडलाइन असल में एक ऐसा कथन है, जिसका श्रेय आमतौर पर फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। सैन्य संदर्भ में, इसका मूल अर्थ यह है कि जब आपका विरोधी कोई गलती कर रहा हो या कोई भारी पड़ने वाला कदम उठा रहा हो, तो ऐसे में बीच में दखल देने के बजाय, चुपचाप उसे देखते रहना ही ज़्यादा समझदारी होती है। कवर इमेज भी प्रतीकात्मक है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एकदम साफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की इमेज धुंधली है। यह इस बढ़ती हुई वैश्विक सोच को दिखाता है कि एक अस्थिर दुनिया में बीजिंग को फ़ायदा हो सकता है, जबकि वॉशिंगटन मध्य-पूर्व की उथल-पुथल में उलझा हुआ है। जब ट्रंप ने यह टकराव शुरू किया था, तब उनके मन में यह बात नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना है कि तेल के बहाव को कंट्रोल करने से दुनिया के मंच पर ताक़त मिलती है। वेनेज़ुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने और देश के विशाल कच्चे तेल के भंडार पर कब्ज़ा करने के लिए उनका साहसी ऑपरेशन इस बात के काफ़ी संकेत देता है। ईरान के ऊर्जा बहाव को अमेरिका के कंट्रोल में लाना उनकी लिस्ट में अगला काम था। ट्रंप इसका इस्तेमाल चीन के साथ सौदेबाज़ी के लिए एक हथियार के तौर पर कर सकते थे, जो ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। दोनों नेताओं के बीच अगले महीने बीजिंग में एक मुलाक़ात तय है। लेकिन ईरान ज़्यादा मज़बूत साबित हुआ। उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करके अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता खेल दिया है; यह एक ऐसा अहम जलमार्ग है जिससे दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा तेल और गैस गुज़रता है। इस तरह, ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया है।

अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद भी हो जाए, तो चीन को उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान का खास दोस्त होने के नाते चीन को पिछले कुछ हफ्तों में ‘शैडो फ्लीट्स’ (पुरानी और बिना बीमा वाली जहाजों की फौज) के जरिए लाखों बैरल ईरानी तेल मिला है। यही नहीं, चीन ने समझदारी दिखाते हुए आठ अलग-अलग देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिसका उसे अब बड़ा फायदा मिल रहा है। असल में, बीजिंग सालों से ऐसे ही बुरे वक्त की तैयारी कर रहा था।

अभियान

जहां सांसों में बसती है आस्थाः श्रीकालहस्ती की अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा

भारत की आध्यात्मिक विरासत में ऐसे अनेक तीर्थस्थल हैं, जो केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, प्रकृति और परमात्मा के गहरे संबंधों को अनुभव करने का माध्यम बनते हैं। आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित श्रीकालहस्ती मंदिर ऐसा ही एक दिव्य स्थल है, जहां पहुंचते ही व्यक्ति को यह अहसास होने लगता है कि वह किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा के बीच खड़ा है, जो उसकी आत्मा तक को स्पर्श कर रही है। यहां की हवा, यहां का वातावरण और यहां की आस्था मिलकर एक ऐसा अदृश्य संसार रचते हैं, जो हर आगंतुक को भीतर तक प्रभावित करता है।

श्रीकालहस्ती मंदिर को भगवान शिव के वायु स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। पंचभूत स्थलों में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन पांच प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो प्रकृति के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायु तत्व, जो जीवन का आधार है और हर जीव की सांसों में प्रवाहित होता है, यहां एक सजीव अनुभूति के रूप में उपस्थित रहता है। यही कारण है कि इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत गहरा है।

जब श्रद्धालु इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें एक ऐसी अनुभूति होती है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। बिना किसी बाहरी स्रोत के भी वहां एक हल्की हवा का प्रवाह महसूस होता है। यह हवा न तो सामान्य होती है और न ही केवल प्राकृतिक, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति का संकेत देती है, जो अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव अपने वायु स्वरूप में वहां उपस्थित हों और अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हों।

यह अनुभव केवल एक क्षणिक एहसास नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर गहराई तक उतर जाता है। जो भी यहां आता है, वह इस अनोखी अनुभूति को अपने साथ लेकर जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे गर्भगृह में खड़े होते हैं, तो उन्हें एक अलग ही शांति और संतुलन का अनुभव होता है, जैसे उनकी सारी चिंताएं और तनाव उस हवा के साथ बह गए हों।

मंदिर में स्थित शिवलिंग भी अपनी विशेषताओं के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह शिवलिंग वायु तत्व का प्रतीक है और इसकी पूजा अत्यंत विशेष विधियों के साथ की जाती है। यहां की परंपरा के अनुसार, इस शिवलिंग को कोई भी मानव सीधे स्पर्श नहीं करता। यहां तक कि पुजारी भी इसे हाथ नहीं लगाते और अभिषेक केवल अनुष्ठानिक तरीकों से ही किया जाता है। यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि यहां की शक्ति सामान्य नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य है।

श्रद्धालुओं के बीच यह मान्यता भी प्रचलित है कि यहां दर्शन और पूजा करने से अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है। विशेष रूप से हृदय, फेफड़े और पेट से संबंधित बीमारियों में लाभ मिलने की बात कही जाती है। हालांकि यह विश्वास आस्था पर आधारित है, लेकिन यहां आने वाले लोगों के अनुभव इस बात को और भी मजबूत बनाते हैं कि इस स्थान पर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है।

श्रीकालहस्ती मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि इसका प्रारंभिक स्वरूप एक छोटे से पूजा स्थल के रूप में था, जिसे स्थानीय जनजातियों द्वारा पूजित किया जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी ने किया था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। इन तीनों की भक्ति और समर्पण के कारण ही इस स्थान का नाम श्रीकालहस्ती पड़ा, जिसमें ‘श्री’ मकड़ी, ‘काल’ सांप और ‘हस्ती’ हाथी का प्रतीक है।

यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और समर्पण किसी भी रूप में हो सकते हैं। चाहे वह एक साधारण जीव ही क्यों न हो, यदि उसमें सच्ची श्रद्धा है, तो वह भगवान के निकट पहुंच सकता है। यही संदेश इस मंदिर की आत्मा में समाहित है।

समय के साथ इस मंदिर का विस्तार विभिन्न राजवंशों के संरक्षण में हुआ। पल्लव, चोल और विजयनगर जैसे राजाओं ने इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने यहां विशाल गोपुरम, सुंदर मंडप और जटिल नक्काशी का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी कला और स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण हैं। मंदिर की दीवारों पर बने शिलालेख और चित्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे इतिहास के साक्ष्य भी हैं।

मंदिर का राजगोपुरम विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है, जिसकी ऊंचाई और भव्यता दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा मंदिर के विभिन्न मंडप, जैसे नंदी मंडप, राहु-केतु मंडप और कल्याण मंडप, अपनी-अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंडपों के स्तंभों पर की गई नक्काशी में रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं की झलक मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है।

श्रीकालहस्ती मंदिर का ज्योतिषीय महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह स्थान राहु और केतु ग्रहों से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहां की राहु-केतु पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां इस पूजा के लिए आते हैं, ताकि वे अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति पा सकें। मान्यता है कि इस पूजा के माध्यम से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राहु और केतु ने यहां भगवान शिव की आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें ग्रहों का दर्जा प्राप्त हुआ। यही कारण है कि यह स्थान उनके पूजन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहां की पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह लोगों के मन में विश्वास और आशा का संचार भी करती है।

मंदिर में हर वर्ष मनाया जाने वाला कल्याणोत्सव भी अत्यंत भव्य और महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का भी कार्य करता है।

आज के आधुनिक जीवन में, जहां लोग तनाव और भागदौड़ से घिरे हुए हैं, ऐसे में श्रीकालहस्ती मंदिर जैसे स्थान एक सुकून भरा आश्रय प्रदान करते हैं। यहां की हवा, यहां की शांति और यहां की आस्था व्यक्ति को भीतर से संतुलित और शांत बनाती है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारी आस्था में निहित है। अंततः, श्रीकालहस्ती मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जो हर व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार करता है। यहां की हवा में जो दिव्यता है, वह हर उस व्यक्ति को स्पर्श करती है, जो सच्चे मन से यहां आता है। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और भविष्य में भी अपनी इसी विशेषता के कारण लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर: दिल्ली में येलो अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी और 10 राज्यों में बदला मौसम का मिजाज

(जीएनएस)। देशभर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और इसकी वजह बना है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जिसने उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तक अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में जहां रुक-रुक कर बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और भूस्खलन जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं। इस बदलते मौसम ने एक ओर जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कई क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों से राजधानी में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। आसमान में बादल छाए रहने, हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग और लोधी रोड पर 1.8 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि आयानगर, पालम, पीतमपुरा, पूसा, मयूर विहार और जनकपुरी सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली। इस बारिश का असर यह हुआ कि तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले पांच दिनों तक यानी 13 अप्रैल तक बारिश की संभावना कम हो जाएगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ का सबसे अधिक प्रभाव पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। जम्मू क्षेत्र में तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है, जिससे ठंड का असर फिर से महसूस किया जा रहा है। रामबन जिले में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ा है, जो सामान्य से काफी नीचे चला गया है। चंडीगढ़ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग पांच डिग्री कम है। लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और अन्य शहरों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है।
राजस्थान में भी इस मौसम प्रणाली का असर स्पष्ट रूप से देखा गया है। जोधपुर के फलोदी में 42.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र के लिए एक उल्लेखनीय आंकड़ा है। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। इससे जहां किसानों को कुछ राहत मिली है, वहीं कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और बारिश ने कई जिलों को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव ने गर्मी की शुरुआत को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं भी सामने आई हैं।
आईएमडी के अनुसार, 8 अप्रैल को उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं 9 और 10 अप्रैल को पहाड़ी राज्यों में छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का असर बना रह सकता है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही गर्मी का असर बढ़ रहा था।
विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी मौसमी प्रणाली है जो भूमध्यसागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में पहुंचती है और बारिश तथा बर्फबारी का कारण बनती है। यह मुख्य रूप से सर्दियों में सक्रिय रहती है, लेकिन कभी-कभी गर्मी के शुरुआती महीनों में भी इसका असर देखने को मिलता है।
इस बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने न केवल मौसम को ठंडा किया है, बल्कि कई राज्यों में तापमान को सामान्य से नीचे ला दिया है। हालांकि, इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, तेज हवाएं और ओलावृष्टि, जो जनजीवन और कृषि दोनों को प्रभावित कर सकती हैं।
फिलहाल मौसम विभाग की सलाह है कि लोग सतर्क रहें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि वहां भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
कुल मिलाकर, पश्चिमी विक्षोभ के इस प्रभाव ने देश के बड़े हिस्से में मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और नागरिकों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। आने वाले दिनों में मौसम किस तरह करवट लेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

अप्रैल में जनवरी जैसा मौसम, उत्तर भारत में ठंड और तबाही का डबल असर

(जीएनएस)। उत्तर भारत में इस बार मौसम ने ऐसा करवट बदला है कि अप्रैल का महीना जनवरी जैसा महसूस होने लगा है। आमतौर पर इस समय जहां तेज धूप और गर्मी की शुरुआत हो जाती है, वहीं इस साल तेज हवाएं, लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे मौसम चक्र को उलट कर रख दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और ट्राइसिटी—चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला—में देखने को मिल रहा है।
चंडीगढ़ में 7 अप्रैल को अधिकतम तापमान मात्र 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.4 डिग्री कम है। पिछले पांच वर्षों में यह अप्रैल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। यह बदलाव केवल तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि हवा की तीव्रता, बादल छाए रहना और बीच-बीच में हो रही ओलावृष्टि ने पूरे क्षेत्र में सर्दियों जैसा माहौल बना दिया है।
लेकिन इस बदले मौसम का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। पंजाब और हरियाणा देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, और यह समय फसल के पकने और कटाई का होता है। खेतों में खड़ी सुनहरी फसल, जो कटाई के लिए पूरी तरह तैयार थी, अब तेज हवाओं और बारिश के कारण जमीन पर बिछ चुकी है। कई जगहों पर ओलों ने बालियों को तोड़ दिया, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है।
किसानों के लिए यह दोहरी मार साबित हो रही है। एक तरफ खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, तो दूसरी तरफ जो किसान अपनी फसल काटकर मंडियों तक ले आए थे, उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडियों में बारिश से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण गेहूं भीग रहा है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है और बाजार में सही कीमत मिलने की संभावना कम हो रही है।
किसानों का कहना है कि अप्रैल में इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि बेहद असामान्य है। गेहूं की फसल को पकने के लिए सूखा और गर्म मौसम चाहिए होता है, ताकि दाने अच्छी तरह सूख सकें। लेकिन लगातार हो रही बारिश ने इस पूरी प्रक्रिया को बाधित कर दिया है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। Indian National Congress ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि पहले ही किसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे और अब इस बेमौसम बारिश ने उनकी कमर तोड़ दी है। पार्टी ने सरकार से तुरंत मुआवजा देने और राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है।
वहीं Bharatiya Janata Party ने पंजाब सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि यदि फसल बीमा योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया होता, तो किसानों को इस समय राहत मिल सकती थी। बीजेपी का कहना है कि न तो व्यापक स्तर पर फसल बीमा हुआ है और न ही समय पर गिरदावरी कराई गई है, जिससे किसान आर्थिक संकट में फंस गए हैं।
इन आरोप-प्रत्यारोप के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार इस स्थिति को गंभीरता से ले रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी कराई जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके और प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसम परिवर्तन केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) का संकेत हो सकता है। मौसम के पैटर्न में इस तरह का अचानक बदलाव आने वाले समय में खेती के पारंपरिक चक्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे किसानों की अनिश्चितता और बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, यह स्थिति केवल मौसम की नहीं, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था और राजनीति—तीनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर आने वाले महीनों में खाद्य आपूर्ति और किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हादसा और हिंसा अधीर रंजन के काफिले पर टक्कर, कई घायल; अलग-अलग जगहों पर बढ़ा सियासी टकराव

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल जैसे-जैसे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक तनाव भी गहराता जा रहा है। हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना सामने आ रही है, जो यह संकेत देती है कि इस बार का चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि साख और शक्ति का भी बड़ा संघर्ष बन चुका है। इसी क्रम में मुर्शिदाबाद जिले से सामने आई एक घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता Adhir Ranjan Chowdhury के काफिले की एक गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

यह घटना उस समय हुई जब अधीर रंजन चौधरी कांडी क्षेत्र में अपना चुनावी प्रचार अभियान समाप्त कर बहरामपुर की ओर लौट रहे थे। शाम करीब 6:45 बजे जिबंती इलाके के पास अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने काफिले की एक गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारी घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
घटना के तुरंत बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि राहत की बात यह रही कि अधीर रंजन चौधरी खुद इस दुर्घटना में सुरक्षित रहे, लेकिन उनके काफिले पर हुआ यह हमला कई सवाल खड़े कर गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे सामान्य सड़क दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए साजिश की आशंका जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से ट्रक ने सीधे काफिले को निशाना बनाया, वह संदेह पैदा करता है।
कांग्रेस के स्थानीय कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बात को लेकर पार्टी नेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। उनका आरोप है कि प्रशासन की यह उदासीनता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और यह दर्शाती है कि विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
इसी के समानांतर राज्य के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हुगली जिले के बांडेल क्षेत्र से सामने आई घटना ने इस तनाव को और हवा दे दी है। यहां एक स्थानीय निवासी प्रदीप ने आरोप लगाया कि देर रात उनके घर और वाहन पर पत्थरबाजी की गई। उनके मुताबिक रात करीब 2 बजे अचानक शीशा टूटने की आवाज आई और जब वे बाहर आए तो देखा कि खिड़की का कांच टूट चुका था और उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे।
प्रदीप का दावा है कि उन्होंने हमलावरों को पहचान लिया है और वे Bharatiya Janata Party के समर्थक हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित झूठ बताया है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है।
सिलीगुड़ी में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। यहां Bharatiya Janata Party और All India Trinamool Congress के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। दोनों दल एक-दूसरे पर पोस्टर हटाने, झंडे उतारने और राजनीतिक गतिविधियों में बाधा डालने के आरोप लगा रहे हैं। यह विवाद तब और बढ़ गया जब टीएमसी उम्मीदवार Gautam Deb ने इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
इसके जवाब में बीजेपी उम्मीदवार Shankar Ghosh ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित तौर पर सत्ताधारी पार्षद के परिवार के सदस्य भाजपा का झंडा हटाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन यहां भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि टीएमसी की शिकायतों पर तुरंत कदम उठाया जाता है। इसी नाराजगी के चलते शंकर घोष ने पुलिस अधिकारियों को घेरकर कड़ी फटकार लगाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। यह घटना बताती है कि चुनावी माहौल में प्रशासन की निष्पक्षता कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसकी कमी कैसे हालात को और बिगाड़ सकती है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो साफ होता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब टकराव, अविश्वास और आरोपों का केंद्र बन चुका है। सड़क हादसे, पत्थरबाजी, पोस्टर विवाद और पुलिस की भूमिका पर उठते सवाल—ये सभी मिलकर एक जटिल और संवेदनशील स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते हालात को नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह तनाव आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे निष्पक्षता बनाए रखें, कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करें और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करें। अंततः यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की असली परीक्षा ऐसे ही समय में होती है। जब माहौल तनावपूर्ण हो, आरोप-प्रत्यारोप अपने चरम पर हों और भावनाएं उफान पर हों, तब प्रशासन की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी ही यह तय करती है कि चुनाव शांतिपूर्ण होंगे या संघर्षपूर्ण।

भारत मे पहली बार 2200 MT क्रेन का कमाल, अहमदाबाद में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर पर रचा इतिहास

1360 टन वजनी पोर्टल बीम का सफल लॉंच,मणिनगर–अहमदाबाद रेलखंड पर बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में मुम्बई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना के अंतर्गत आज मणिनगर–अहमदाबाद रेलखंड पर अत्यंत जटिल एवं उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस क्रम में किमी 497 (BKC/Mumbai से दूरी) पर स्थित पियर संख्या 05 पर प्रीकास्ट आरसीसी पोर्टल बीम का सफल प्रक्षेपण (Launching) किया गया, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है।

इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश तथा PCPM/NHSRCL, अहमदाबाद श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति एवं निगरानी में कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
उक्त पोर्टल बीम अत्यंत विशाल एवं भारी संरचना है, जिसका वजन लगभग 1360 टन है। इसकी लंबाई 34 मीटर, चौड़ाई 5.5 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इसे M50 ग्रेड कंक्रीट से निर्मित किया गया है, जिससे इसकी संरचनात्मक मजबूती एवं दीर्घायु सुनिश्चित होती है।
इस जटिल कार्य के निष्पादन हेतु 2200 टन क्षमता वाली अत्याधुनिक क्रॉलर क्रेन (SANY SCC38000TM) का उपयोग किया गया, जिसका भारतीय रेलवे में प्रथम बार प्रयोग किया गया है। यह क्रेन उच्च स्तरीय सुपर-लिफ्ट तकनीक से युक्त है, जो भारी-भरकम संरचनाओं को सुरक्षित एवं नियंत्रित ढंग से स्थापित करने में सक्षम है।
इस विशाल क्रेन के विभिन्न हिस्सों को लगभग 110 ट्रेलरों के माध्यम से साइट तक पहुँचाया गया, जहाँ विशेषज्ञ इंजीनियरों की निगरानी में सटीक एवं चरणबद्ध तरीके से असेम्बली कार्य संपन्न किया गया। यह प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत जटिल एवं तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी। इस उन्नत तकनीक एवं सुव्यवस्थित योजना के उपयोग से न केवल कार्य की दक्षता में वृद्धि हुई, बल्कि समय की उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित हुई तथा उच्चतम सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया।
कार्य के सफल निष्पादन हेतु मणिनगर–अहमदाबाद रेलखंड पर लगभग 03 घंटे 30 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया। इस अवधि के दौरान सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया गया तथा ब्लॉक समाप्ति के पश्चात रेल यातायात को सुचारु रूप से बहाल कर दिया गया।
इस प्रकार के जटिल कार्य के लिए पूर्व नियोजित चरणबद्ध तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें प्री-कास्टिंग, लिफ्टर अटैचमेंट, ट्रायल लिफ्टिंग, क्रेन पोजिशनिंग, सुपर-लिफ्ट ऑपरेशन, बीम लिफ्टिंग एवं अंतिम स्थापना जैसे सभी महत्वपूर्ण चरणों का समुचित समन्वय किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्य क्षेत्र में उपस्थित ओएचई (OHE), सिग्नलिंग उपकरणों एवं अन्य अवरोधों का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी विस्थापन एवं पुनर्स्थापन सुनिश्चित किया गया।
परियोजना के आगामी चरणों में इसी प्रकार के अन्य पोर्टल बीमों—P06, P07, P08 एवं P09—का प्रक्षेपण भी निर्धारित है, जिन्हें लगभग प्रत्येक 6 दिनों के अंतराल पर क्रमिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इन सभी पोर्टल बीमों का वजन लगभग 1070 टन से 1110 टन के मध्य है तथा इन्हें उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया है।
मुम्बई से आने वाली बुलेट ट्रेन का एलाइन्मेंट मणिनगर क्षेत्र में पारंपरिक रेलवे के तीनों ट्रैकों (UP, DN एवं 3rd Line) को क्रॉस करते हुए ओल्ड रेलवे कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड, कांकरीया क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा आगे अहमदाबाद स्टेशन होते हुए साबरमती मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब की दिशा में अग्रसर होता है।
इस संदर्भ में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट के माध्यम से उल्लेख किया कि—
"गुजरात के मणिनगर में बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत सबसे भारी गिर्डर्स में से एक का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसका वजन लगभग 1,360 मीट्रिक टन है तथा इसे मात्र 3.5 घंटे के निर्धारित समय में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।"
उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की अत्याधुनिक हेवी-लिफ्ट तकनीक के उपयोग से पारंपरिक विधियों की तुलना में कार्य की गति, सटीकता एवं सुरक्षा स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे एवं हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत आधुनिक अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

क्रूड ऑयल वायदा 1920 रुपये लुढ़का: सोना वायदा में 3011 रुपये और चांदी वायदा में 14323 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 228650.6 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 35009.3 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 193641.19 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36813 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5382.12 करोड़ रुपये का हुआ।
कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 23293.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 153550 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 154934 रुपये और नीचे में 152693 रुपये पर पहुंचकर, 150289 रुपये के पिछले बंद के सामने 3011 रुपये या 2 फीसदी बढ़कर 153300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 2754 रुपये या 2.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 122580 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 341 रुपये या 2.27 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15356 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मई वायदा 151000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153390 रुपये और नीचे में 151000 रुपये पर पहुंचकर, 3270 रुपये या 2.2 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152003 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 150999 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153697 रुपये और नीचे में 150999 रुपये पर पहुंचकर, 149023 रुपये के पिछले बंद के सामने 3431 रुपये या 2.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152454 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 240601 रुपये के भाव पर खूलकर, 246376 रुपये के दिन के उच्च और 240601 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 231348 रुपये के पिछले बंद के सामने 14323 रुपये या 6.19 फीसदी की मजबूती के साथ 245671 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 14463 रुपये या 6.18 फीसदी की बढ़त के साथ 248317 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 14448 रुपये या 6.18 फीसदी की मजबूती के साथ 248400 रुपये प्रति

किलो बोला गया।
मेटल वर्ग में 2787.30 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 26.5 रुपये या 2.29 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1186.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 1.35 रुपये या 0.41 फीसदी की तेजी के संग 330.35 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1 रुपये या 0.28 फीसदी औंधकर 354.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 30 पैसे या 0.15 फीसदी की नरमी के साथ 195.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।
इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8836.57 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 10243 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 10243 रुपये और नीचे में 8749 रुपये पर पहुंचकर, 1920 रुपये या 18 फीसदी औंधकर 8749 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1920 रुपये या 18 फीसदी की गिरावट के साथ 8747 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 262 रुपये के भाव पर खूलकर, 262 रुपये के दिन के उच्च और 253.8 रुपये के नीचले स्तर को

▸▸ कॉटन वायदा में 110 रुपये और मेंथा तेल वायदा में 4.20 रुपये की नरमी: कपास वायदा 66 रुपये और इलायची वायदा 17 रुपये बढ़ा: कमोडिटी वायदाओं में 35009 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 193641 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 23293 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36813 पॉइंट के स्तर पर

छूकर, 269.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 14 रुपये या 5.19 फीसदी लुढ़ककर 255.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 13.8 रुपये या 5.11 फीसदी गिरकर 256.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।
कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 1051 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.20 रुपये या 0.41 फीसदी गिरकर 1019 रुपये प्रति किलो हुआ। कॉटन अप्रैल वायदा प्रति गांठ 28500 के भाव पर खूलकर, 110 रुपये या 0.38 फीसदी की नरमी के साथ 28500 रुपये के स्तर पर ही स्थिर रहा। जबकि कपास का अप्रैल वायदा प्रति 20 किलो 1651 रुपये के स्तर पर खूलकर, ऊपर में 1716 रुपये और नीचे में 1651 रुपये के स्तर को छूकर 66 रुपये या 4 फीसदी की बढ़त के साथ 1716 रुपये पर पहुँचा। इलायची का अप्रैल वायदा प्रति किलो 2570 रुपये के भाव पर खूलकर, ऊपर में 2670 रुपये और नीचे में 2570 रुपये के स्तर पर पहुँचकर 17 रुपये या 0.64 फीसदी की वृद्धि के साथ 2669 रुपये हुआ।
कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16078.73 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7214.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1963.40 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 388.92 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 13.18 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 415.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7127.04 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1674.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.07 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8230 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 49212 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 24982 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 368474 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 54631 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6993 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19383 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 75474 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15633 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 41818 लोट के स्तर पर था।
इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 36813 पॉइंट पर खूलकर, 36813 के उच्च और 36813 के नीचले स्तर को छूकर, 1040 पॉइंट बढ़कर 36813 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।
कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 1059.9 रुपये की गिरावट के साथ 185 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.65 रुपये की गिरावट के साथ 10.3 रुपये हुआ।
सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 121 रुपये की बढ़त के साथ 582 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 177.5 रुपये की बढ़त के साथ 882 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.07 रुपये की बढ़त के साथ 19.15 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो बिना बदलाव के 4.88 रुपये हुआ।
पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 148.5 रुपये की बढ़त के साथ

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की पूर्व तैयारियों के निरीक्षण एवं अध्ययन के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम की पहली गुजरात यात्रा

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट से स्पोर्ट टीम ने गुजरात यात्रा का प्रारंभ किया
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए टाइम बाउंड, क्वालिटेटिव और इफेक्टिव प्लानिंग के मंत्र से शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को टीमवर्क से सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष ने ग्लासगो में 23 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया
- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष और सीईओ ने भारत और गुजरात के साथ उत्साहपूर्ण सहयोग से शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को शानदार सफलता मिलने की अपेक्षा व्यक्त की
- गुजरात की यात्रा के दौरान टीम अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और एकतानगर में आयोजित होने वाले सीडब्ल्यूजी 2030 के खेल स्थलों का साइट विजिट करेगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में अहमदाबाद में 2030 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की अहमदाबाद सहित कई शहरों में जोरों शोरों से चल रही पूर्व तैयारियों के निरीक्षण तथा अध्ययन के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम पहली बार गुजरात की आधिकारिक यात्रा पर आई है।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इस टीम के पांच सदस्य इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान गुजरात में ठहरेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट से इस प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात यात्रा की शुरुआत की। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड रुकारे और सीईओ सुश्री केटी सैडलेयर ने गुजरात में उन्हें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए टाइम बाउंड, क्वालिटेटिव तथा इफेक्टिव प्लानिंग के मंत्र को साकार करते हुए शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए टीमवर्क से कार्य करते हुए इन खेलों का भव्य आयोजन करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।

श्री डोनाल्ड ने उल्लेख करते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में आयोजित होने जा रहे हैं, ऐसे में गुजरात को मिला इसका मेजबान पद अत्यंत गौरवपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और खेलों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को विश्वास दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से उपलब्ध कराएगी।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष और सीईओ ने आगामी जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को देखने और वहां के कार्य-प्रबंधन के अध्ययन तथा निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि गुजरात का प्रतिनिधिमंडल ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भाग लेगा।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड रुकारे ने गुजरात में आयोजित होने वाले 2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स को सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने वाला खेल उत्सव बनाने के लिए पारस्परिक टीमवर्क से कार्य करने की उत्सुकता दर्शाई।

गुजरात की इस यात्रा के दौरान कॉमनवेल्थ स्पोर्ट डेलीगेशन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के खेल स्थलों; अहमदाबाद का वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स, नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, ईकेए एरेना तथा वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम और एकता नगर - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पूर्व तैयारियों के निरीक्षण और अध्ययन के लिए साइट विजिट करेगा।

इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ प्रधान सचिव श्री अश्विनी कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात के महानिदेशक श्री वाळा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जितेंद्र कुमार जयंत ने आज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अहमदाबाद के सलाहकार जनसंपर्क के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे पर वर्ष 1992 में सीधे जनसंपर्क विभाग में इंदौर में पदभार ग्रहण किया था तत्पश्चात जो जून 1996 में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जयपुर मंडल पर नियुक्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा के मूल निवासी जयंत ने अपनी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री तथा आगरा कॉलेज आगरा से विधि स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात के.एम. हिंदी इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ़ मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेने के पश्चात रेलवे में पदार्पण किया था । जयंत IRCTC अहमदाबाद में बतौर पुनः नियोजन के आधार पर नियुक्त किया गया है, वह 31 अगस्त 2024 में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल से वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी "ग्रुप ए" के रूप में सेवा निवृत हुए थे ।

जयंत का आईआरसीटीसी अहमदाबाद में पद ग्रहण करने के पश्चात नई दिल्ली स्तर , मुंबई मुख्यालय स्तर तथा अहमदाबाद क्षेत्रीय स्तर पर आईआरसीटीसी के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जिससे आम जन समुदाय को सही जानकारी और भरपूर फायदा मिल सके।

हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: मजदूरी में 35% बढ़ोतरी से लेकर अग्निवीरों को दोगुना आरक्षण तक, सरकार के अहम कदम

(जीएनएस)। हरियाणा में Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दिशा तय करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी। इस बैठक में लिए गए निर्णय सीधे तौर पर मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले हैं। खास बात यह रही कि सरकार ने एक साथ कई वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत बदलाव किए, जिन्हें आगामी समय में बड़ा असर डालने वाला माना जा रहा है।

सबसे बड़ा और चर्चा में रहने वाला फैसला रहा न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 11,257 प्रति माह से बढ़ाकर 15,220 प्रति माह कर दिया है, जो लगभग 35% की बढ़ोतरी है। यह कदम लाखों मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे श्रमिकों के सम्मान और आर्थिक मजबूती की

दिशा में बड़ा निर्णय बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

दूसरा बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर लिया गया है। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% के बजाय 20% तक हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। खास तौर पर फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में यह आरक्षण लागू होगा। सरकार का मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त अग्निवीर अनुशासन, शारीरिक दक्षता और फील्ड अनुभव के कारण इन पदों के लिए उपयुक्त होंगे।

वृद्धजनों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। यह बदलाव बुजुर्गों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही, टीडीआर नीति 2021 के अनुरूप इन परियोजनाओं को अधिक लचीलापन दिया गया है, जिससे निवेश और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राशन डिपो आवंटन में 33% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। इसमें भी एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस के लिए न्यूनतम 300 राशन कार्ड की जगह 500 राशन कार्ड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिपो धारकों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तक की जा सकती है, बशर्ते उनका कार्य संतोषजनक हो। यदि किसी डिपो धारक का निधन हो जाता है, तो उसके कानूनी वारिस को डिपो आवंटित करने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे परिवार की आजीविका प्रभावित न हो।

भूमि से जुड़े मामलों में भी कैबिनेट ने अहम संशोधन किया है। हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम, 1964 में नया नियम 5A जोड़ा गया है। इसके तहत उन परियोजनाओं को राहत दी जाएगी, जिनके पास पर्याप्त रास्ता (पैसेज) नहीं है। अब ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि के एक हिस्से का हस्तांतरण कर रास्ता उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।

इन सभी फैसलों को समग्र रूप से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा सरकार ने एक संतुलित नीति अपनाने की कोशिश की है, जिसमें मजदूर, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और उद्योग—सभी को शामिल किया गया है। जहां एक ओर मजदूरी बढ़ाकर गरीब वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों को आरक्षण देकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

पोरबंदर – आसनसोल के बीच 13 अप्रैल से प्रत्येक सोमवार को चलेगी "साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन",टिकटों की बुकिंग 10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से प्रारंभ होगी

(जीएनएस)। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अतिरिक्त यात्री सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के अंतर्गत विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन विशेष किराया (Special Fare) पर संचालित की जाएगी। यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा पोरबंदर और आसनसोल के बीच "साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन" संचालित की जाएगी। यह सेवा अप्रैल 2026 से जून 2026 के मध्य दोनों दिशाओं में कुल 12-12 फेरों के साथ चलाई जाएगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

ट्रेन नंबर 09205 पोरबंदर – आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल 13 अप्रैल, 2026 से 29 जून, 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन पोरबंदर से प्रत्येक सोमवार को सुबह 8.50 बजे प्रस्थान कर बुधवार को सुबह 6.45 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 09206 आसनसोल – पोरबंदर साप्ताहिक स्पेशल 15 अप्रैल, 2026 से 01 जुलाई, 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन आसनसोल से प्रत्येक बुधवार को रात्रि 23.05 बजे प्रस्थान कर शुक्रवार को रात्रि 21.50 बजे पोरबंदर पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भाणवड, लालपुर जाम, जामनगर, हापा, राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर जं., विरमगाम, अहमदाबाद, आणंद, छायापुरी, गोधरा जं., रतलाम, नागदा जं., उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, ललितपुर, विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जं., गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ओन सोन, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन गोमो, धनबाद जं. स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर तथा जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन नंबर 09205 के लिए टिकटों की बुकिंग 10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रीगण ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सेवा का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाएं।

ज्योतिषी एम. चौधरी का आरोप: आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, विधायकों पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाला मेवाड़ा द्वारा) सूरत. तापी जिले के सामाजिक नेता और नवी सिविल अस्पताल के सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी ज्योतिष एम. चौधरी ने आदिवासियों की दिन-प्रतिदिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों का शोषण करके चुने गए विधायकों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। गुजरात में समाज के नाम पर चुने गए विधायक समाज को भूल जाते हैं। उनमें समाज के प्रति समर्पण की भावना का अभाव है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा आवंटित करोड़ों रुपये कहां जाते हैं, यह समझ से परे है। अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में वर्षों से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कड़ी मेहनत से स्नातक होने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रोजगार नहीं मिलता। वर्तमान में ऐसे कई युवा बेरोजगार हैं। माध्यमिक

विद्यालय या उससे कम पढ़े-लिखे युवाओं के पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य सरकार और निगम बोर्डों में लाखों रिक्तियां होने के बावजूद, सरकार ने ठेका प्रणाली लागू कर अपना हिस्सा ले लिया है। जिसके कारण ठेके पर काम करने वाले युवाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। जब तक समाज जागरूक नहीं होता और समाज में से समर्पित नेताओं को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाता, तब तक उनके विकास या स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि वर्तमान विधायक केवल अपने ही विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज के युवाओं के बारे में कौन सोचेगा?

पश्चिम रेलवे द्वारा असारवा–आगरा कैंट असारवा विशेष ट्रेन का नियमितीकरण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 01920/01919 असारवा–आगरा कैंट–असारवा स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अब सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी, जिससे हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा तथा रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस निर्णय के अंतर्गत ट्रेन संख्या 01920/01919 को नियमित ट्रेन संख्या 20177/20178 असारवा–आगरा कैंट–असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 20177 (असारवा–आगरा कैंट) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 से, सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार एवं बुधवार को छोड़कर) असारवा से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:15 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 20178 (आगरा कैंट–असारवा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिनांक 08 अप्रैल, 2026 से, सप्ताह में 5 दिन (सोमवार एवं मंगलवार को छोड़कर) आगरा कैंट से 18:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:00 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं बयाना जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर एवं जनरल सेकंड श्रेणी के कोच शामिल होंगे।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

अमेरिका-ईरान सीजफायर पर कश्मीर नेता बोले युद्ध टला, पाकिस्तान की भूमिका भी सराही गई

(जीएनएस)। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिदृश्य के बीच जब दुनिया एक बड़े युद्ध की आशंका से घिरी हुई थी, तब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर एक राहत की खबर बनकर सामने आया। लेकिन इस वैश्विक घटनाक्रम की गूंज भारत के जम्मू-कश्मीर तक भी सुनाई दी, जहां राजनीतिक बयानबाज़ी ने इस मुद्दे को एक नया आयाम दे दिया। खासतौर पर महबूबा मुफ्ती के बयान ने इसे केवल अंतरराष्ट्रीय घटना तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे भारत-पाकिस्तान संबंधों और कश्मीर की राजनीति से भी जोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस सीजफायर को "मुबारक दिन" बताते हुए कहा कि बीते दिनों में जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, उससे पूरी दुनिया में भय और अस्थिरता का माहौल बन गया था। हालात ऐसे बन चुके थे कि किसी भी वक्त यह टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता था।

उन्होंने कहा कि ईरान ने जिस हिम्मत और धैर्य के साथ इस चुनौती का सामना किया, वह सराहनीय है। उनके अनुसार यह केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्र के आत्मसम्मान और उसके अस्तित्व की लड़ाई भी थी। इसी बयान के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का योगदान अहम रहा है और उसने दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह कथन तुरंत ही राजनीतिक बहस का कारण बन गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। ऐसे में एक प्रमुख भारतीय नेता द्वारा पाकिस्तान की खुले तौर पर तारीफ करना कई सवाल खड़े करता है। यह बयान उनके उस पुराने रुख को भी दर्शाता है, जिसमें वे लगातार भारत-पाकिस्तान के बीच संवाद और सहयोग की बात करती रही हैं।

दूसरी ओर मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस सीजफायर का स्वागत करते हुए कहा कि यह शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि दुनिया को अब टकराव के बजाय संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके अनुसार ईरान ने जिस संयम और साहस का परिचय दिया, वह वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण है। उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह युद्धविराम स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इसी क्रम में फारूक अब्दुल्ला का बयान एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को सामने लाता है। उन्होंने कहा कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और अंततः देशों को बातचीत के रास्ते पर ही लौटना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर यह संघर्ष और लंबा चलता, तो इसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता था, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाती। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इस युद्ध का असर उन लाखों लोगों पर पड़ता, जो खाड़ी देशों में काम करते हैं और जिनकी आजीविका इन क्षेत्रों पर निर्भर है। जम्मू-कश्मीर के भी कई परिवार ऐसे हैं, जिनके सदस्य विदेशों में काम करते हैं, और इस तरह के संघर्ष उनके जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में सामने आएगा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आज की दुनिया में कोई भी संघर्ष केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव वैश्विक होता है और उसकी राजनीतिक गूंज दूर-दूर तक सुनाई देती है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां की राजनीति पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होती रही है।

महबूबा मुफ्ती का बयान जहां एक ओर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखाता है कि कश्मीर की राजनीति में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं मीरवाइज और फारूक अब्दुल्ला के बयान यह संकेत देते हैं कि शांति और संवाद की आवश्यकता को लेकर व्यापक सहमति है, भले ही उसे व्यक्त करने के तरीके अलग-अलग हों। अंततः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह सीजफायर केवल एक कूटनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि बातचीत और समझदारी की जरूरत है।